

राजनीतिक

- **क्या वे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे ?**

राजनीतिक गलियारों में तेजस्वी सूर्या (कर्नाटक), श्रीकांत शिंदे (महाराष्ट्र), प्रियंका रावत (उत्तर प्रदेश) और शमिक भट्टाचार्य को मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने की अटकलें तेज हैं।

- **उत्तर प्रदेश में मौलाना समाजवादी पार्टी से मुस्लिम मुख्यमंत्री उम्मीदवार की मांग कर रहे**

उत्तर प्रदेश में मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी समेत कुछ मौलानाओं ने अखिलेश यादव से इस बार किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 22 प्रतिशत है और यादव की 7 प्रतिशत, इसलिए इस बार पार्टी को किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह इसे स्वीकार करेंगे?

- **गांधी परिवार की छवि में बदलाव की अंदरूनी प्रक्रियाः कनुगोलू और पूर्व नौकरशाह नई रणनीति का नेतृत्व कर रहे**

सोनिया गांधी की किताब के प्रकाशन के बाद, गांधी परिवार ने नागरिकों से दूरी कम करने के उद्देश्य से अपनी छवि को सुनियोजित तरीके से बदलने का प्रयास किया है। सूत्रों के अनुसार, राजनीतिक रणनीतिकार सुनील कानूगोलू एक पूर्व नौकरशाह के साथ मिलकर इस रणनीतिक छवि सुधार की योजना बना रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य परिवार की सार्वजनिक छवि को नरम बनाना है ताकि वे आम कांग्रेसी मतदाता और व्यापक जनता दोनों के लिए अधिक सहज और भरोसेमंद प्रतीत हों। स्पष्ट बातचीत और अधिक सुलभ संदेशों के माध्यम से, ये दोनों मिलकर जनता की धारणा को बदलने और जमीनी स्तर पर गहरा जुड़ाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

- **कॉर्पोरेट हाउस कौन सा है ?**

ऐसी अफवाहें हैं कि कोई कॉरपोरेट घराना किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बेदखल करना चाहता है। क्या आप कोई अनुमान लगा सकते हैं?

प्रशासनिक

- **ओडिशा के डीजीपी पद की दौड़ के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही भुवनेश्वर में लॉबिंग चरम पर पहुंची**

भुवनेश्वर के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर चल रहा है क्योंकि ओडिशा के मौजूदा पुलिस महानिदेशक 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पैनल में शामिल करने की बातचीत और ज़ोरदार पैरवी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, ऐसे में इस बदलाव को राज्य की भाजपा सरकार के लिए एक अग्निपरीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता कथित तौर पर पिछली सरकार की प्रशासनिक शैली से निर्णायक रूप से अलग होने के लिए दबाव बना रहे हैं। चूंकि पूर्व बीजद सरकार के करीबी माने जाने वाले कई नौकरशाहों को दरकिनार किया जा सकता है, वहीं अंदरूनी सूत्रों का अनुमान है कि डीजीपी की नियुक्ति से आने वाले हफ्तों में प्रमुख जिलों और खुफिया विभागों में पुलिस बल में व्यापक फेरबदल होगा।

- **क्या भारत में भी लगातार बिजली कटौती की समस्या आने वाली है ?**

अमेरिका के बुनियादी ढांचे में लगातार हो रही रुकावटों के बाद, भारत के संबंधित मंत्रालय और विभाग हाई अलर्ट पर हैं और महत्वपूर्ण प्रणालियों को ठीक करने और अपडेट करने के लिए वॉर रूम स्थापित कर रहे हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि भारत में भी इसी तरह के हमले हो सकते हैं क्योंकि घरेलू नेटवर्क में समान सॉफ्टवेयर निर्भरता और कॉन्फ़िगरेशन संबंधी कमजोरियां हैं। अधिकारी जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक सार्वजनिक और उद्यम सेवाओं में तेजी से कमजोरियों का आकलन करने, घटना प्रतिक्रिया समन्वय और पैच जारी करने को प्राथमिकता दे रहे हैं।विश्लेषकों का कहना है कि हालांकि बढ़ी हुई सतर्कता और युद्ध कक्ष में सक्रियता से तैयारी मजबूत होती है, लेकिन पुरानी अवसंरचना और जटिल आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रमुख दबाव बिंदु बनी हुई हैं। यदि विदेशों में व्यापक व्यवधान उत्पन्न होते हैं, तो भारतीय रक्षा बलों के पास जोखिमों को नियंत्रित करने और महत्वपूर्ण डिजिटल संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीमित समय होगा।

- **क्या बालेन शाह द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए एक पत्र ने संबंधों को फिर से सुधारने में मदद की?**

प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह के नई दिल्ली में गर्मजोशी से स्वागत और भारत के 15,000 करोड़ रुपये के बाढ़ पुनर्निर्माण पैकेज के पीछे एक अप्रत्याशित मोड़ हो सकता है। अगस्त में रसुवा में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद, शाह के निजी संदेश में भारत द्वारा त्वरित बचाव और आपातकालीन सहायता की प्रशंसा ने संभवतः महीनों से चली आ रही भू-राजनीतिक झिझक को दूर कर दिया। साउथ ब्लॉक में, काठमांडू के इस अनूठे नेता की सच्ची कृतज्ञता ने लंबे समय से चली आ रही शंकाओं को दूर कर दिया होगा, जिससे भारत एक सतर्क पड़ोसी से अपरिहार्य भागीदार के रूप में उभर कर सामने आया और उनकी महत्वाकांक्षी संयुक्त विकास योजना को साकार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

- **हितेंद्र मल्होत्रा रेलवे बोर्ड के सदस्य नियुक्त**



हितेंद्र मल्होत्रा, जो वर्तमान में रेलवे बोर्ड में महानिदेशक (सुरक्षा) के पद पर कार्यरत हैं, को 1 दिसंबर, 2026 से प्रभावी रूप से रेलवे बोर्ड में सदस्य (ट्रैक्शन और रोलिंग स्टॉक) और भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस) के पदेन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वे भारतीय रेलवे विद्युत अभियंता सेवा (आईआरएसईई) के अधिकारी हैं।

- **आईआईएस अधिकारी अन्नादुराई ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया**

आईआईएस अधिकारी एम. अन्नादुरई ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के लिए आवेदन किया है। यदि आवेदन स्वीकार हो जाता है, तो उनकी वीआरएस 1 जनवरी, 2027 से प्रभावी होगी। वे 1995 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में दिल्ली में पीआईबी के एडीजी के पद पर तैनात हैं।

- **ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर**

न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 में यह प्रावधान है कि न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग द्वारा गठित खोज-सह-चयन समितियों की सिफारिशों पर की जाएगी। समिति की अध्यक्षता राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के एक न्यायिक सदस्य द्वारा की जाएगी और इसमें एक तकनीकी सदस्य, एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत सरकार के एक सचिव, दो सूचीबद्ध विशेषज्ञ और आयोग के सचिव सदस्य सचिव के रूप में शामिल होंगे।

- **उत्तर प्रदेश आईएएस पदोन्नति चक्र 2027 में पांच बैचों को कवर करेगा**

उत्तर प्रदेश में 2027 में आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति और सेवा श्रेणी में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है, जिसमें 2002, 2011, 2014, 2018 और 2023 बैच के अधिकारी शामिल होंगे। जहां वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नति के लिए 2002 बैच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, वहीं अन्य बैचों के अधिकारियों पर विभिन्न कैरियर-ग्रेड उपलब्धियों के लिए विचार किया जाएगा।

सपा की सरकार में एक भी भर्ती ईमानदारी के साथ नहीं होती थी : योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने 1594 अभ्यर्थियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को इंदिरगांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक हजार 594 सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। मुख्यमंत्री योगी ने युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। पहले की सरकारों में मेधा का सम्मान नहीं था। आज की सरकार में मेधा को ही आगे किया जा राह है। सपा की सरकार में एक भी भर्ती ईमानदारी के साथ नहीं होती थी

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 से पहले उप्र की स्थिति क्या थी, यह सबको पता है। नौ साल पहले एचसीएल में 100 लोग काम करते थे। आज उनके कैम्पस में 18 हजार लोग कार्य कर रहे हैं। 60 फीसदी युवतियां कार्य कर रही हैं। उनसे मैने बात किया तो उन्होंने तीन सिफ्ट में काम कर रहे हैं। देर रात में कार्य करके अपने घर जाते हैं। पहले ऐसा नहीं हो सकता था। रात में लड़कियां नहीं निकल सकती थीं। सरकार में बैठे लोग ही बालिकाओं के लिए खतरा थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपने युवाओं को पढ़ाएंगे नहीं, उन्हें तकनीक के साथ जोड़ेंगे नहीं तो भविष्य कैसे ठीक रहेगा। आज यूपी का युवा इस क्षेत्र को लीड कर रहा है। जो लोग कट्टा और बम बनाते थे, उनकी सोच उतनी ही थी। दुनिया की सबसे अच्छी रायफल यूपी में बन रही है। सबसे अच्छी मिसाइल ब्रह्मोस लखनऊ में ही बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में हमारे यूपी के युवा कार्य



कर रहे हैं। पाकिस्तान पर एक मिसाइल दागी जाती है तो वह बाप-बाप कर चिल्लाता नजर आता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सपा की सरकार में एक भी भर्ती ईमानदारी के साथ नहीं होती थी। 2015-16 के दौरान आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एक परिणाम आया था। जो टॉपर था, वह हाईस्कूल में थर्ड डिवीजन था। इंटरमीडिएट थर्ड डिवीजन, यूजी की जो डिग्री ली थी, उसमें भी थर्ड डिवीजन और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में एसडीएम और टॉप कर गया। टॉप किया नहीं टॉप करवाया गया था। इसीलिए जब मैं आज आपके चेहरे की चमक को देख रहा हूं तो यह चमक केवल आपके चेहरे की नहीं है यह यूपी की चमक है नए यूपी की चमक है।

योगी ने कहा कि मेरिट को नजरअंदाज करना पाप है। पिछले की सरकारों ने मेधावियों को नजरअंदाज किया। हमने उन्हें उसकी सजा दी। आप लोग अपने परिवार को बताइए, दोस्तों को बताइए कि मेरिट की क्या कीमत है। मेरी और वित्त मंत्री द्वारा आप पर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं। आपकी मेहनत का नतीजा है। अगले 10 दिनों में ही हम 50 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। अखिलेश जी आप भी बता दीजिए कि 30 लाख युवाओं को कहां नियुक्ति पत्र देंगे। आप अपने अतीत के बारे में बताएं। आपका अतीत ठीक नहीं है तो भविष्य भी ठीक नहीं हो सकता। वे कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देंगे। सपा के लोग यह भी बताएं कि न्यू पेंशन स्कीम किसने लागू की थी, ये समाजवादी पार्टी ने 2005 में लागू किया था। युवाओं से अपील करते हुए योगी ने कहा कहा कि इसलिए सबको बताएं कि मेरिट का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। अब यूपी पर कोई संदेह नही कर सकता। लोग अपनी सत्ता बचाने के लिए इतना अंधविश्वास और पाखंड में डूबे हुए थे, कहते थे नोयडा जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। राममंदिर का विरोध करेंगे। नोयडा जाएंगे तो कुर्सी चली जायेगी, प्रभु से डरो पाखंड से नही। नोएडा, ग्रेटर नोएडा यूपी का इकोनॉमिक फेस है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने इकोनॉमिक फेस को नजरंदाज कर अपने गुर्गों को लूट खसोट करने की परमिशन देता हो, क्या करेंगे आप उसे। इस अवसर पर नवचयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मौके पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अलावा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही।

मेघालय के वन संरक्षण मॉडल का अध्ययन कर रहा उत्तराखंड का 13 सदस्यीय दल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, देहरादून : उत्तराखंड में पारंपरिक जल स्रोतों (धारा-नौला) के पुनर्जीवन और सामुदायिक वन संरक्षण को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य का एक दल मेघालय के संरक्षण मॉडल का अध्ययन कर रहा है। स्प्रिंग्स एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी (एसएआरआरए) और चम्पावत की धारा-नौला संरक्षण समितियों का 13 सदस्यीय संयुक्त दल 25 से 27 नवंबर तक शिलांग के तीन दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर है।

भ्रमण दल में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा वन एवं ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी शामिल हैं। इस दौरान मेघालय बेसिन डेवलपमेंट अथॉरिटी और मेघालय बेसिन मैनेजमेंट एजेंसी के अधिकारियों ने दल को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से वित्तपोषित 'मेगालाइफ' और जर्मन विकास बैंक से वित्तपोषित 'मेगाराइज' परियोजनाओं की कार्यप्रणाली से अवगत कराया।

दल ने मेगालाइफ परियोजना के तहत संचालित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान (पीईएस) मॉडल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मॉडल के तहत प्राकृतिक वन संरक्षण करने वाली स्थानीय समितियों को प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस व्यवस्था में गठित समितियों में 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है।

शिलांग के एक गांव की समिति ने इस पहल के तहत 46 से 47 हेक्टेयर वन क्षेत्र का संरक्षण किया है। वर्तमान में समिति के खाते में सामुदायिक विकास कार्यों के लिए करीब 15 लाख रुपये जमा हैं। इस मॉडल के माध्यम से स्थानीय समुदायों को वन संरक्षण से सीधे आर्थिक लाभ मिल रहा है। भ्रमण के दौरान एसएआरआरए के उपनिदेशक एवं मुख्य वित्त अधिकारी ने क्षेत्र में स्थापित बायोचार उत्पादन संयंत्र का भी निरीक्षण किया। मई 2026 में मेघालय बेसिन डेवलपमेंट अथॉरिटी, किसान उत्पादक कंपनी और एक निजी संस्था के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत यह पायलट परियोजना शुरू की गई थी। इसके माध्यम से बायोचार उत्पादन और उससे अर्जित होने वाले कार्बन क्रेडिट का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस पहल में कोर कार्बन एक्स के प्रतिनिधि तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे हैं। दल ने मेघालय में कृषि वानिकी की तकनीकों का भी अध्ययन किया।

देव दीपावली दीप और पटाखे जलाकर मनाई

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, लखनऊ : देव दीपावली के अवसर पर फर्स्ट स्टेप रिहैबिलिटेशन सोसाइटी के द्वारा पूर्वांचल छठ घाट पुराना हैदराबाद पर हजारों दिए जलाकर और आतिशबाजी कर देव दीपावली बड़ी धूम धाम से मनाई गई तथा सभी श्रद्धालुओं ने एक-एक दीप जलाकर अपना दीपदान किया पंडित शर्मिला महाराज ने बताया कि इस घाट पर प्रतिवर्ष हम लोग देव दीपावली मनाते हैं और यहां पर सभी श्रद्धालु पूर्णिमा के अवसर पर दीए जलाकर अपना अपना दीपदान करते हैं।

संस्था की ओर से यहां सभी श्रद्धालुओं के दिए और तेल की व्यवस्था कराई जाती है ताकि किसी को भी कोई अपना दीपदान करने में असुविधा न हो कार्यक्रम संयोजक पंडित मनीष महाजन ने बताया कि अगले वर्ष और भव्यता से कार्यक्रम



कराया जाएगा मनोहर रंगोली वी कलाकृतियां भी बनाई जाएगी और इस वर्ष जो कमियां रह गई थी जैसे लाइट उसको भी अगले वर्ष दूर किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से लखनऊ विश्वविद्यालय पूर्व अध्यक्ष प्रमोद तिवारी, पूर्व महामंत्री अनिल सिंह बीरू, ज्ञानू शुक्ला, मनोज, निसार हुसैन रिजवी, विकास श्रीवास्तव, सुमित कश्यप, अधिवक्ता साथी विक्रम श्रीवास्तव, शिवांगी द्विवेदी, आयशा, अमित वर्मा, रवि वर्मा, पप्पू यादव, प्रमोद शुक्ला, हरि राजभर, विजय यादव, अरविंद गुप्ता, सर्वेश चौरसिया, कल्लू सोनकर, दीपक चंद, आशीष मौर्या सहित सैकड़ो लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

चुनाव से पहले ईवीएम व वीवीपैट जागरूकता अभियान शुरू

नईदुनिया राज्य ब्यूरो, देहरादूनः उत्तराखंड में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के दृष्टिगत इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ईवीएम) और मतदाता सत्यापन पर्ची मशीन (वीवीपैट) के उपयोग को लेकर जन-जागरूकता कार्यक्रम शुरू हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने मतदाताओं से कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच पूरी होने के बाद प्रशिक्षण एवं जागरूकता के लिए 974 मतदान इकाइयां, 974 नियंत्रण इकाइयां और 974 वीवीपैट मशीनें निर्धारित की गई हैं। यह प्रक्रिया मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्धारित मानकों के अनुसार पूरी की गई। प्रशिक्षण के लिए चिन्हित मशीनों की सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है। इन मशीनों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार अलग गोदाम में रखा जाएगा। मतदान प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन करने के लिए प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी के मुख्यालयों पर प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में चलित प्रदर्शन वाहन तैनात किए गए हैं, जो मतदान केंद्रों, गांवों, मोहल्लों, वार्डों और अन्य समूहों तक पहुंचकर मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया समझाएंगे। निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने तक यह अभियान जारी रहेगा। घोषणा के बाद ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित जागरूकता केवल डिजिटल माध्यमों से प्रसारित की जाएगी। अभियान के दौरान प्रदर्शन केंद्रों की जानकारी संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजी जाएगी।

निराश्रित नहीं, अब 'एकल नारी' के नाम से पहचानी जाएंगी महिलाएँः सीएम धामी

उत्तराखंड में 'मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना' लागू



नईदुनिया राज्य ब्यूरो, देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने विधवा, परित्यक्ता और निराश्रित अविवाहित महिलाओं के भरण-पोषण के लिए संचालित अनुदान योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना कर दिया है। अब तक यह योजना निराश्रित महिला भरण-पोषण अनुदान के नाम से संचालित थी। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर समाज कल्याण विभाग को जानकारी दे दी है।

योजना के दायरे में तीन श्रेणियों की महिलाएं शामिल हैं। इनमें निराश्रित विधवाएं, परित्यक्ता विवाहित महिलाएं और निराश्रित अविवाहित महिलाएं शामिल हैं। इन तीनों श्रेणियों के लिए संचालित भरण-पोषण अनुदान योजना को अब एक साझा नाम दिया गया है। समाज कल्याण सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्धांकी ने निदेशक समाज कल्याण को पत्र भेजकर योजना के नाम में संशोधन की जानकारी दी है। शासन के आदेश के बाद अब विभागीय स्तर पर योजना को नए नाम से संबोधित किया जाएगा। योजना के नाम में बदलाव के पीछे महिलाओं को सम्मानजनक सामाजिक पहचान देने का उद्देश्य बताया गया है। अब तक योजना के नाम में निराश्रित शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि नए नाम में एकल नारी शब्द को प्राथमिकता दी गई है। इस बदलाव के माध्यम से विधवा, परित्यक्ता और निराश्रित अविवाहित महिलाओं को एक साझा पहचान के तहत लाने का प्रयास किया गया है। सरकार का मानना है कि नाम में बदलाव महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को अधिक सम्मानजनक बनाने की दिशा में एक कदम है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना नामकरण का उद्देश्य एकल महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है। सरकार की ओर से जारी आदेश में फिलहाल केवल योजना के नाम में बदलाव की जानकारी दी गई है।

अनुदान की राशि, पात्रता संबंधी नियमों और लाभार्थियों की संख्या में किसी बदलाव का उल्लेख नहीं किया गया है। योजना के तहत पहले से निर्धारित सहायता व्यवस्था के संबंध में अलग से कोई संशोधन घोषित नहीं किया गया है।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग की 6.59 किलोमीटर सुरंग आर-पार

ऋषिकेश। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण कार्य में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। रुद्रप्रयाग जिले में परियोजना की 6.59 किलोमीटर लंबी सुरंग संख्या-14 के दोनों छोरों को जोड़ दिया गया। इसके साथ ही सुरंग की दोनों ओर से चल रही खुदाई का काम पूरा होकर आपस में जुड़ गया। रेल मंत्रालय के अनुसार, सुरंग की खुदाई सुमेरपुर स्थित पहले छोर और मारोड़ा स्थित दूसरे छोर से की जा रही थी। दोनों तरफ से लगातार खुदाई के बाद शुक्रवार को मुख्य सफलता मिली। सुमेरपुर की ओर से 4.7 किलोमीटर और मारोड़ा की ओर से 1.79 किलोमीटर खुदाई की गई। इस तरह दोनों हिस्सों को जोड़कर 6.59 किलोमीटर लंबी सुरंग का रास्ता तैयार हो गया। सुरंग निर्माण के दौरान आबादी वाले क्षेत्र के नीचे खुदाई करना सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल रहा। करीब 110 मीटर आबादी के नीचे काम करते समय कमजोर भूगर्भीय परिस्थितियों के कारण निर्माण कार्य में विशेष सावधानी बरतनी पड़ी। जमीन धंसने की आशंका और आसपास की बस्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य किया गया।

आपका राशिफल 28 नवम्बर

मेष चू चे चो ला ली लू ले लो आ — अध्ययन-अध्यापन में समय गुजरेगा। ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि होगी और सज्जनों का साथ भी रहेगा। कुछ कार्य भी सिद्ध होंगे। व्यर्थ की भाग दौड़ से यदि बचा ही जाए तो अच्छा है। प्रियजनों से समागम का अवसर मिलेगा। अवरुद्ध कार्य संपन्न हो जाएंगे। धर्म-कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी। शुभांक-1-4-6

वृष इ उ ए ओ वा वी वू वे वो — महत्त्वपूर्ण निर्णय के लिए दूरदर्शिता से काम लें। कोष में कमी व व्यय की अधिकता से परेशान होंगे। किसी से वाद-विवाद अथवा कहासुनी होने का भय रहेगा। जल्दबाजी में कोई भूल संभव है। कार्य भार बढ़ेगा। स्वविवेक से कार्य करें। कार्यक्षेत्र में तनाव पैदा होगा। समय व्ययकारी सिद्ध होगा। शुभांक-2-5-7

मिथुन का की कू घ ङ छ के को हा — परिश्रम प्रयास से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। प्रपंच में ना पड़कर काम पर ध्यान दीजिए। कल का परिश्रम आज लाभ देगा। लेन-देन में अस्पष्टता ठीक नहीं। स्वास्थ्य लाभ में समय और धन व्यय होगा। अच्छे समय इन्तजार करें। कर्म प्रधान विचार धारा बनाये रखें। नैतिक दायरे में रहें। शुभांक-3-6-7

कर्क ही हू हे हो डा डी डू डे डो — सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छे कार्य के लिए रास्ते बना लेंगे। अपने हित के काम सुबह-सवेरे ही निपटा लें। रुपए पैसों की सुविधा नहीं मिल पाएगी। यात्रा प्रवास का सार्थक परिणाम मिलेगा। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। मनोबल ऊंचा रखें और काम में लगे रहें। शुभांक-4-6-8

सिंह मा मी मू मे मो टा टी टू टे — अपने काम में सुविधा मिल जाने से प्रगति होगी। नवीन जिम्मेदारी बढ़ने के आसार रहेंगे। यात्रा शुभ रहेगी। अपने काम को प्राथमिकता से करें। आगे बढ़ने के अवसर लाभकारी सिद्ध हो रहे है। कार्यक्षेत्र में संतोषजनक सफलता मिलेगी। कल का परिश्रम आज लाभ देगा। साक्षात्कार के लिए दिन शुभ रहेगा। शुभांक-5-8-9

कन्या टो पा पी पू ष ण ठ पे पो — कुछ पिछले संकट अब सिर उठा सकते हैं। अपने संघर्ष में स्वयं को अकेला महसूस करेंगे। अभिष्ट कार्य सिद्ध होंगे। निकटजनों के लिए अर्थव्यवस्था हेतु जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। बुरी संगति से बचें। सुविधाओं में शनैः-शनैः बाधा आएगी। वरिष्ठ लोगों से कहासुनी के कारण तनाव पैदा हो सकता है। शुभांक-4-7-9

तुला श री रु रे शे ता ती तू ते — पूर्व में किये कार्यों से लाभ मिलेगा। मानसिक एवं शारीरिक शिथिलता पैदा होगी। अपने हितैषी समझे जाने वाले ही पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपना काम दूसरों के सहयोग से पूरा होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शांतिपूर्वक कार्य करें। धार्मिक यात्रा का योग हैं। शुभांक-5-7-9

वृश्चिक तो ना नी नू ने नो य यी यू — दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। कामकाज में आ रही बाधा दूर होगी। बाहरी और अंदरूनी सहयोग मिलता चला जाएगा। पर प्रपंच में ना पड़कर अपने काम पर ध्यान दीजिए। लेन-देन में आ रही बाधा को दूर करने में सफल होंगे। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। व्यापार में स्थिति ठीक रहेगी। शुभांक 2 5 9

धनु ये यो आ भी भू धा फा ढा भे — संतोष रखने से सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थिति सामान्य ही रहेगी। शैक्षणिक क्षेत्र में उदासीनता रहेगी। जीवनसाथी का परामर्श लाभदायक रहेगा। व्यापार व नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी। कल का परिश्रम आज लाभ देगा। कामकाज में आ रही बाधा दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। शुभांक-4-6-8

मकर भे जा जी खी खू खे खो गा गी — मनोरथ सिद्ध होंगे, पूरे मनोयोग से काम में लगे रह। बाहरी और अंदरूनी सहयोग मिलता चला जाएगा। पर प्रपंच में ना पड़कर अपने काम पर ध्यान दीजिए। लेन-देन में आ रही बाधा को दूर करने के प्रयास सफल होंगे। धार्मिक कार्य में समय और धन व्यय होगा। कारोबारी काम में बाधा बनी रहेगी। शुभांक-3-5-7

कुंभ गू गे गो ग्रा शी शू शे शो ढा — स्वास्थ्य में ताजगी बनी रहने से नई ऊर्जा का संचार होगा। संतोष रखने से सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थिति सामान्य ही रहेगी। शैक्षणिक क्षेत्र में उदासीनता रहेगी। जीवनसाथी का परामर्श लाभदायक रहेगा। व्यापार व नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ कार्यों का लाभदायक परिणाम होगा। शुभांक-6-9-9

मीन दी दू थ झ ञ दे दो चा ची — सुनियोजित तरीके से कार्य आरम्भ करें, सफल होंगे। लाभ भी होगा और पुराने मित्रों का समागम भी। धर्म-कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी। श्रेष्ठजनों की सहानुभूतियां होगी। रुका हुआ लाभ आज प्राप्त हो सकता है। आमोद-प्रमोद का दिन होगा और व्यावसायिक प्रगति भी होगी। शुभांक-3-6-7

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लिया निर्णय

छूटे आंदोलनकारियों को मिलेगा चिन्हीकरण का मौका

नईदुनिया राज्य ब्यूरो, देहरादूनः उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के बावजूद अब तक राज्य आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित होने से वंचित रह गए लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। राज्य सरकार ऐसे शेष आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण के लिए नई प्रक्रिया निर्धारित करेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने तय किया है कि अब तक चिन्हीकरण से छूट गए राज्य आंदोलनकारियों को सूची में शामिल करने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया तैयार की जाएगी। इसके माध्यम से उन लोगों को भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने का अवसर मिल सकेगा, जिन्होंने राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन किसी कारणवश पूर्व में संचालित चिन्हीकरण अभियान में उनका नाम दर्ज नहीं हो पाया था।



सरकार के इस निर्णय को राज्य आंदोलनकारियों के लंबे समय से लंबित मुद्दे के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उद्देश्य पात्र आंदोलनकारियों को उनका उचित सम्मान और नियमानुसार मिलने वाले लाभ उपलब्ध कराना है।

उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को लंबे जनआंदोलन के बाद हुआ था। राज्य निर्माण की मांग को लेकर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने आंदोलन किया था। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने धरना-प्रदर्शन, जुलूस और अन्य गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय भागीदारी निभाई थी। हालांकि, चिन्हीकरण की पूर्व प्रक्रिया के दौरान कुछ आंदोलनकारी सूची में शामिल होने से रह गए थे। ऐसे लोगों की ओर से लगातार चिन्हीकरण का अवसर देने की मांग की जाती रही है। कैबिनेट के फैसले के बाद अब सरकार इस दिशा में आगे की प्रक्रिया तैयार करेगी। संबंधित विभाग चिन्हीकरण के लिए पात्रता और आवश्यक नियम निर्धारित करेगा। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आवेदन किस माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, किन दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में मान्यता दी जाएगी और चिन्हीकरण की प्रक्रिया के लिए क्या समयसीमा तय होगी।

सरकार की ओर से इन बिंदुओं पर आगे निर्णय लिया जाएगा। नई प्रक्रिया लागू होने के बाद चिन्हीकरण से वंचित रह गए पात्र आंदोलनकारियों को अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने का अवसर मिल सकेगा।